13-03-2024

डीआरडीओ का 'मिशन दिव्यास्त्र'

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि-5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- 'मिशन दिव्यास्त्र 'नामक यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
- मिशन दिव्यास्त्र एक ऐसा मिशन है जिसमें एक ही मिसाइल को विभिन्न युद्ध स्थलों पर निशाना बनाकर तैनात किया जा सकता है | यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च सटीकता सेंसर पैकेजों से लैस है|
- मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक उस तकनीक को कहते है जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है | इन हथियारों से दुश्मन के अलग-अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है|

अग्नि 5 मिसाइल के बारे में

- अग्नि 5 मिसाइल एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (Inter-Continental Ballistic Missile-ICBM) है जो अग्नि सीरीज की 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है|
- भारत ने दिसंबर 2022 में परमाणु क्षमता से लैस अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था|
- अग्नि-5 एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Programme- IGMDP) के तहत विकसित सतह-से-सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है।
- यह दागो और भूल जाओ मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता है।
- अग्नि-1 से 5 मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई हैं।

24वां उद्यमिता केंद्र - "फिनग्लोब" का शुभारंभ

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त समिति, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने गुजरात के गांधीनगर, गिफ्ट सिटी में अपना 24वां उद्यमिता केंद्र (सीओई) - "फिनग्लोब" का शुभारंभ किया। यह समिति वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समर्पित है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- फिनग्लोब उद्यमिता केंद्र (सीओई), गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना है।
- फिनग्लोब उद्यमिता केंद्र (सीओई) अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा, विशेषज्ञ परामर्श और एक सहयोगी

इकोसिस्टम प्रदान करके स्टार्टअप्स, उद्यमियों और स्थापित प्रतिनिधियों को फिनटेक, टेकफिन, बैंकिंग उद्योग और संबद्ध क्षेत्रों में अपने समाधानों को विचार करने, क्षेत्र में नवाचार करने और उसमें वृद्धि करने के लिए सशक्त बनाना चाहता है। उद्यमिता केंद्र (सीओई) 50 प्लग-एन-प्ले इनक्यूबेशन सीटें प्रदान करता है।

- यह फिनटेक उद्यमिता केंद्र (सीओई) स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सैंडबॉक्स वातावरण, इंडस्ट्री एपीआई, पेमेंट गेटवे, मेंटरिंग, इंडस्ट्री और मार्केट कनेक्ट जैसी अपेक्षित सहायता प्रदान करेगा।
- उद्यमिता केंद्र (सीओई) की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि प्रौद्योगिकी में निवेश करके और बदलते रुझानों पर ध्यान देकर, स्टार्टअप वित्तीय प्रणाली के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को बदल सकें।
- यह स्टार्टअप्स के साथ-साथ संभावित निवेशकों को नवीनतम रुझानों के साथ नए उत्पादों और सेवाओं को नया करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

"सुभाष अभिनंदन" का उद्घाटन

सुर्खियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस के अवसर पर कानून एवं न्याय (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी "सुभाष अभिनंदन" का शुभारंभ किया।

- राष्ट्रीय अभिलेखागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को संरक्षित किया गया है| इस प्रदर्शनी में उनके जन्म से लेकर मौजूदा समय तक की अवधि को कवर करने वाले 16 खंड शामिल हैं।
- यह दस्तावेजों के माध्यम से उनके जीवन की एक झलक प्रदान करता है, जिसमें जानकी नाथ बोस की डायरी, उनके जन्म, उनके लोक सेवा परीक्षा परिणाम और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। यह वर्ष 1920 से 1940 तक के संघर्ष के दशकों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, जो उनके भाषणों, उनकी साहसिक यात्रा और आजाद हिंद फौज के संघर्ष की जानकारी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में

- राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संलग्न कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च, 1891 को कोलकाता (कलकत्ता) में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार के मौजूदा भवन का निर्माण वर्ष 1926 में किया गया था, जिसके वास्तुकार सर एडविन लुटियन्स थे।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम - 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम- 1997 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भी है।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार के भंडार में अभी सार्वजनिक अभिलेखों के 34 करोड़ से अधिक पृष्ठों का संग्रह है। इनमें फाइलें, खंड, मानचित्र, भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृत बिल, संधियां, दुर्लभ पांडुलिपियां, प्राचीन रिकॉर्ड, निजी दस्तावेज, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स, राजपत्रों व विवरणिका का महत्वपूर्ण संग्रह, जनगणना रिकॉर्ड, विधानसभा व संसद की बहस, गैर-कानूनी या प्रतिबंधित साहित्य, यात्रा खाते आदि शामिल हैं।

सुभाष चंद्र बोस के बारे में

- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को कटक में हुआ था। इनके जयंती के अवसर पर 'पराक्रम दिवस' मनाया जाता है|
- बोस पहली बार वर्ष 1938 में हरिपुरा में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीँ वर्ष 1939 में त्रिपुरी (Tripuri) में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या (Pattabhi Sitaramayya) के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता।
- उन्होंने एक नई पार्टी 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मज़बूत करना था।
- वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान-नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' का नारा दिया|
- उन्होंने 21 अक्तूबर, 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की।

भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा (Iwaichi Fujiwara) के नेतृत्त्व में किया गया था|

- वर्ष 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मृत्यु हो गई, हालाँकि अभी भी उनकी मृत्यु के संबंध में कई राज छिपे हुए हैं।

ए. एस. राजीव सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त

सुर्खियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को ए.एस. राजीव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली|
- श्री ए.एस. राजीव ने अपने कैरियर में एक बैंकर की तरह कार्य किये हैं, उनके पास चार प्रमुख बैंकों अर्थात् सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक कामकाज का अनुभव है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है, जिसे सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- इस आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में की गई, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।

- यह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केन्द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है।
- इस बहु-सदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) शामिल होते हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष (इनमें जो पहले हो) का होता है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष सुरेश एन. पटेल है।
- CVC किसी भी मंत्रालय/विभाग के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। यद्यपि CVC अपने कार्यकलाप में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, लेकिन उसके पास न तो संसाधन हैं और न ही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्ति है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह या तो CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers- CVO) के माध्यम से मामले की जाँच/अन्वेषण कराता है।

नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन

सुर्खियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली में अपनी तरह की पहली "नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी" - 'डीबीटी स्पीडी सीड्स' का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह पहल किसानों की आय दोगुनी करने, उनके आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने और कृषि-स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता के अनुरूप है|
- इससे किसानों को अब अपनी फसल को गुणात्मक के साथ-साथ मात्रात्मक रूप से भी बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा।

- जैव प्रौद्योगिकी त्वरित बीज (बायोटेक्नोलॉजी स्पीडी सीड्स) सुविधा भारत के सभी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी लेकिन यह विशेष रूप से उत्तर भारतीय राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए उपयोगी होगी।
- यह सुविधा उन्नत फसल की प्रजातियों के विकास में तेजी लाकर फसल सुधार कार्यक्रमों में परिवर्तनकारी बदलावों को बढ़ाएगी जो जलवायु परिवर्तन के दौरान स्वयं को बनाए रख सकती हैं और स्पीड ब्रीडिंग फसल विधियों के कार्यान्वयन के साथ बड़ी जनसंख्या की भोजन और पोषण संबंधी मांग में योगदान कर सकती हैं|
- नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी (एनएबीआई) के डीबीटी संस्थान ने 'जलवायु प्रतिरोधी फसलों' की तकनीक विकसित की है, इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किसानों को किसी विशेष मौसम में फसल उगाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें जलवायु अनुकूलता की परवाह किए बिना खेती करने की स्वतंत्रता होगी।
- गौरतलब है कि वर्तमान सरकार बायो-इकोनॉमी के महत्व के प्रति सचेत है और इसीलिए हाल के 'लेखानुदान बजट (वोट ऑफ अकाउंट-बजट)' में जैव-विनिर्माण (बायो-मैन्युफैक्चरिंग) के लिए एक विशेष योजना का प्रावधान किया गया है।
- इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआई) ने 'अटल जय अनुसंधान बायोटेक (यूएनएटीआई) मिशन (पोषण अभियान) और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि के लिए जैवप्रौद्योगिकी किसान केन्द्रों (बायोटेक किसान हब) में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।